CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 240 ▫ रायपुर, मंगलवार 23 सितम्बर 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच रिपोर्ट भेजी गई केन्द्र को, शिकायतों-आवेदनों का भी हो रही परीक्षण

रायपुर, 23 सितंबर (हाईवे चैनल)। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाला की जांच रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दी गई है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जांच रिपोर्ट की स्क्रूटनी तथा जांच टीम गठित होने के बाद प्राप्त शिकायतों व आवेदनों का परीक्षण भी किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर- विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाला सामने आने के बाद राज्य शासन के निर्देश पर भूअर्जन मुआवजा प्रकरणों की जांच का जिम्मा रायपुर संभाग के आयुक्त को सौंपा गया था. संभागायुक्त ने भारतमाला परियोजना के तहत भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों के संबंध में नए सिरे से दावा- आपत्तियां मंगाई थीं।

संभागायुक्त को डेढ़ सौ से अधिक दावा-आपत्तियां व शिकायतें मिली थीं. इनकी जांच के लिए अपर कलेक्टरों की अध्यक्षता में चार अलग-अलग टीमें बनाई थीं. उन्हें हफ्तेभर के भीतर रिपोर्ट देने कहा गया था. तीन टीमों ने अपनी रिपोर्ट संभागायुक्त को सौंप दी है. केवल एक टीम की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को मुआवजा घोटाला मामले में मांगी गई जानकारी व जांच रिपोर्ट भेज दी गई है. इस बीच जांच टीमों के गठन के बाद मुआवजा वितरण के संबंध में कुछ और शिकायतें व आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों व शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है. साथ ही जांच रिपोर्ट की स्क्रूटनी भी की जा रही है, ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। नए सिरे से प्राप्त दावा-आपत्तियों में अधिकांश किसानों ने अर्जित भूमि का कम मुआवजा मिलने का आरोप लगाया है. हालांकि, ऐसे प्रकरणों में प्रभावित किसान संभागायुक्त के न्यायालय के समक्ष अभ्यावेदन दे सकते हैं। बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्नम सिक्सलेन भूमि अधिग्रहण मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है. एसडीएम, पटवारी और भू-माफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर जमीन को कई टुकड़ों में बांटकर करोड़ों रुपए की मुआवजा राशि निकाल ली गई और शासन को नुकसान पहुंचाया गया।

करेली बड़ी में राज्य स्तरीय महतारी सदन कार्यक्रम में पहुंचे विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री ने 77 कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण, 245 करोड़ की दी सौगात

धमतरी, 23 सितम्बर (हाईवे चैनल)। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में विधानसभा क्षेत्र कुरूद के ग्राम करेली बड़ी में राज्य स्तरीय महतारी सदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री आज बाय रोड रायपुर से करेली बड़ी पहुंचे जहां कार्यक्रम स्थल पर जनप्रनिधियों, अधिकारियों व भाजपा नेताओं द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। सभा के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जिसमें मुख्यमंत्री ने जिले को विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कुरूद विधानसभा क्षेत्र के कुल 77 कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। जिन पर 245.80 करोड़ से अधिक की राशि व्यय होगी। यह कार्य जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल, उद्योग, विज्ञान, पर्यटन और सामाजिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों को नई दिशा देने वाले हैं।

कुरूद क्षेत्र में विकास को मिली गति छत्तीसगढ़ के 51 महतारी सदन का हुआ लोकार्पण

महिला सशक्तिकरण नए भवनों का शिलान्यास- महतारी सदन योजना के तहत 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसमें कुरूद के 4 महतारी सदन भवन शामिल है । नए भवनों का शिलान्यास भी किया गया। लगभग 2.10 करोड़ की लागत से निर्मित ये भवन महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता के नए केंद्र बनेंगे। ये महतारी सदन हमारी माताओं-बहनों की शक्ति और क्षमता को समाज में नई पहचान देंगे।

औद्योगिक, शिक्षा एवं कौशल विकास- ग्राम करेली बड़ी और भालूझूलन में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 16.61 करोड़ की लागत से आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जी-जामगांव 6 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण हुआ। इन कार्यों से उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएँ खुलेंगी। 27.67 करोड़ की लागत वाली शिक्षा और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में आईटीआई भवन, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और लाइवलीहुड कॉलेज भवन का शिलान्यास किया गया। वहीं, 7.53 करोड़ की लागत वाली कृषि महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का लोकार्पण हुआ। ये संस्थान युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास के प्रमुख केंद्र बनेंगे।

सड़क और अधोसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाएँ- जिले के विभिन्न मार्गों के निर्माण और सुधार के लिए 9 सड़क कार्यों का शिलान्यास 119.79 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। साथ ही 1.70 करोड़ लागत वाली गौरव पथ योजना के तहत गातापार और बकली मार्ग का लोकार्पण हुआ। नई सड़कें गाँवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। 75 लाख की लागत से भेण्ड्री में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएँ और अधिक सुलभ होंगी।

पेयजल, सिंचाई, विज्ञान एवं पर्यटन, सामाजिक विकास पर जोर- जल जीवन मिशन के तहत 39 कार्य 29.99 करोड़ की लागत से पूरे होंगे, जिससे जिले की हर बस्ती हर घर जल प्रमाणित होगी। कोडेबोड़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना 26.37 करोड़ और महानदी नहर पर क्रॉस रेग्युलेटर 4.29 करोड़ की लागत से निर्मित होगा। इससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। गंगरेल में साइंस पार्क का निर्माण किया गया है. जो बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन की नई संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। कंवर समाज भवन (मधुबन धाम, राकांडीह) का निर्माण 50 लाख की लागत से होगा, जो सामुदायिक विकास को नई ऊर्जा देगा। इस अवसर पर कुरुद विधायक अजय चन्द्राकर, भानू चन्द्राकर, कुरुद नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चन्द्राकर, भखारा नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योंति जैन, विधायक प्रतिनिधि हरख जैन, आदि उपस्थित रहे।

ब्रेकिंग न्यूज

निर्माणाधीन दुकान में अधेड़ की मिली लाश

गरियाबंद, 23 सितम्बर (हाईवे चैनल)। नगर में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रावणभाठा स्थित कृषि उपज मंडी के सामने एक निर्माणाधीन दुकान में अधेड़ की लाश मिली. मृतक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, वार्ड नंबर 7 रावणभाठा स्थित मंगलवार की सुबह कृषि उपज मंडी के सामने अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली है. मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. हालांकि उसकी उम्र 50 से 55 साल के बीच की आशंका जताई जा रही है. सूचना के बाद थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खां, समर्थकों ने मनाया जश्न

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (न्यूज चैनल)। जिला कारागार से 23 माह बाद मंगलवार करीब 12.20 बजे आजम खां रिहा हो गए हैं। जिला कारागार से दो गाड़ियां बाहर आई हैं। एक गाड़ी में आजम खां चार लोगों के साथ बैठे हैं। इनमें उनके पुत्र अदीब, अब्दुल्ला, उनके प्रतिनिधि व दो अन्य लोग हैं। दूसरी गाड़ी में आजम खां का सामान है। यह वही सामान है, जो उनके साथ कारागार में था। इनमें उनकी किताबें, कपड़े व अन्य सामान शामिल है। बता दें कि आजम खां की रिहाई को लेकर मंगलवार सुबह से ही एलआईयू की टीमें, ड्रोन टीम व पीएसी के जवान मुस्तैद रहे। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह, प्रशिक्षु आईपीएस विनायक भोंसले, यातायात निरीक्षक फरीद अहमद व करीब आठ थानों की फोर्स मौजूद रही।

मशहूर गायक जुबीन गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (न्यूज चैनल)। असम अपने मशहूर गायक जुबीन गर्ग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके अंतिम संस्कार की रस्म कमारकुची एनसी गांव, कमरुप जिला, गुवाहाटी के पास आयोजित की जा रही है। जुबीन का पार्थिव शरीर अर्जुन भोगेश्वर बरूआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अंतिम यात्रा के लिए निकाला गया, जहां जनता को उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। वहीं, सिंगर को अंतिम विदाई देते हुए पत्नी गरिमा की भी झलक सामने आई है।

चूहा- सुनती हो, पीएम मोदी जी का जीएसटी बचत उत्सव कब तक चलेगा।
चुहिया- हां जी, इस बार लंबा चलेगा, बिहार बंगाल, गुजरात चुनाव के बाद दिल्ली चुनाव जो है..!

नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने शांति वार्ता से किया किनारा, हथियार छोड़ने से इंकार

जगदलपुर, 23 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुद्दे पर शांति वार्ता की संभावनाओं को लेकर नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने अपने सुर बदल लिए हैं। केंद्रीय समिति प्रवक्ता अभय और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी प्रवक्ता विकल्प ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि बदली हुई परिस्थितियों में संगठन हथियार नहीं छोड़ेगा।

प्रेस नोट में कहा गया है कि माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू द्वारा हाल ही में शांति वार्ता को लेकर जारी किए गए पत्र से केंद्रीय समिति का कोई संबंध नहीं है। समिति ने इसे व्यक्तिगत राय बताते हुए उससे खुद को अलग कर लिया है। केंद्रीय समिति ने आरोप लगाया कि बसवराजु द्वारा शांति वार्ता को लेकर किये गए प्रयास को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। समिति का कहना है कि शांति वार्ता को लेकर मत जानने का प्रयास करने से संगठन में टूट होगी। हथियारबंद संघर्ष को स्थायी रूप से त्यागना मतलब क्रांतिकारी पार्टी को संशोधनवादी पार्टी में बदलना है। तीन पन्नों के प्रेस नोट में एक बार फिर नक्सलियों ने शांति वार्ता की बात से पलटी मारी है।

अब पुरानी गाड़ियां बेचना गाड़ी मालिकों के लिए महंगा सौदा, नियम हुआ लागू

रायपुर, 23 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियां परिवहन यान और गैर परिवहन यान की दूसरी बार बिक्री पर भी एक प्रतिशत और आधा प्रतिशत टैक्स लगेगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 2025 बनाया था और इसे राज्य विधानसभा से पारित कराया गया था. इस अधिनियम को अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ियां बेचना भी गाड़ी मालिकों के लिए महंगा सौदा बनने जा रहा है. दरअसल, सरकार ने अब ये नियम बना लिया है कि किसी भी गाड़ी की बिक्री पर होने वाले नाम ट्रांसफर पर गैर परिवहन यान के लिए पंजीयन के समय वाहन के मूल्य की एक प्रतिशत राशि देनी होगी. परिवहन यान (माल वाहकों) के लिए यही शुल्क आधा प्रतिशत लगेगा।

राज्य सरकार ने यह बदलाव लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम में 5 हजार से लेकर 14 हजार तक तथा चारपहिया गाड़ियों में 7 हजार रुपए से लेकर पौने दो लाख रुपए तक गिरावट आई है. जीएसटी कम किए जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक के साथ दोपहिया एवं चारपहिया गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ गई है, जिसके कारण सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों एवं वाहन शो रूम में खरीदारों की दिनभर भीड़ लगी रही. राडा अध्यक्ष रविंदर बसीन ने बताया कि चारपहिया वाहन में छोटी गाड़ियों में 10 प्रतिशत एवं लग्जरी गाड़ियों में 15 से 22 प्रतिशत तक जीएसटी घटाया गया है, है, वहीं यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के संचालक पवन डागा ने बताया कि एलईडी टीवी, एसी एवं डिस ड्रेनर मशीन में 10 प्रतिशत जीएसटी कम हुआ है. इन उपकरण में पहले 28 प्रतिशत जीएसटी था. इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रानिक्स सामान में पहले से 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, इसलिए इनकी कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है।

राज्य सरकार द्वारा वाहनों के अंतरण (ट्रांसफर) के लिए जो शुल्क लगाया जा रहा है उसके विश्लेषण से ये बात सामने आ रही है एक गाड़ी का पहली बार पंजीयन होने के समय वाहन के मानक मूल्य के हिसाब से राशि मिलेगी. इसके बाद यही गाड़ी आठगे जितनी बार बिकेगी, हर बार पंजीयन के समय वाहन के मानक मूल्य की एक प्रतिशत राशि मालिक को देनी पड़ेगी. जैसे अगर कोई कार दस लाख रुपए की है और वह अगली बार जैसे ही बिकेगी या नाम ट्रांसफर होगा तो उसके पंजीयन के मानक मूल्य की एक प्रतिशत राशि यानी 10 हजार रुपए फीस परिवहन विभाग को देनी पड़ेगी. यही गाड़ी जितनी बार बिकती जाएगी, सरकार के खजाने में एक प्रतिशत की दर से राशि आती जाएगी. इसी तरह परिवहन यान के लिए यह राशि आधा प्रतिशत यानी 0.5 प्रतिशत लगेगी। इसी संशोधन के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट श्रेणी के वाहनों की टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इसके तहत इन वाहनों से मासिक या त्रैमासिक टैक्स लिया जाता था, इसकी जगह अब गाड़ी के पंजीयन के समय ही लाइफटाइम टैक्स देना पड़ेगा. यही नहीं अगर इस प्रकार के वाहनों के मालिकाना हक बदला गया या बेचा गया तो एक बार फिर मानक पंजीयन मूल्य का आधा प्रतिशत के बराबर शुल्क मालिक को अदा करना पड़ेगा. इस तरह के वाहनों या इक्युमेंट के लिए सरकार ने नई परिभाषा भी तय की है. इसमें लोडर, डंपर, मोबाइल क्रेन, बेकहो लोडर, का काम करने वाले वाहन और इसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े उपकरणों, मशीनों पर भी यह नियम लागू होगा।

भारत के बिना अमेरिका अधूरा, चीन और रूस पर दिया सख्त संदेश : रुबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (न्यूज चैनल)। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान रुबियो ने कहा कि भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । उन्होंने कहा कि भारत के योगदान बिना अमेरिका का विकास अधूरा है।

बैठक में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, दवाइयों, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। रुबियो ने भारत सरकार की लगातार भागीदारी की सराहना की और कहा कि दोनों देश मिलकर रणनीतिक क्षेत्रों में प्रगति को और तेज़ करेंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग जारी रखेंगे।

यह बैठक ऐसे समय हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए एच-वीबी वीज़ा पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर शुल्क लगाने का आदेश जारी किया है। इसका सीधा असर भारतीय आईटी और मेडिकल पेशेवरों पर पड़ा है। साथ ही, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ भी लगा दिया है, जिससे कुल शुल्क दर 50त्न हो गई है- जो दुनिया में सबसे अधिक है। जयशंकर और रुबियो की बैठक उसी दिन हुई, जब भारत और अमेरिका ने एक नए व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में अमेरिकी पक्ष से मुलाकात कर रहा है, ताकि आपसी लाभकारी समझौते तक जल्द पहुँचा जा सके।

छत्तीसगढ़ में हापा एक्सप्रेस हादसा: सीनियर सेक्शन इंजीनियर और मेट को रेलवे ने किया निलंबित

और अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज

रायपुर/ बिलासपुर, 23 सितंबर (हाईवे चैनल)। पोरबंदर-शालीमार हापा एक्सप्रेस (12905) के रेलडाली से टकराने के मामले में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है. एसएसई (सीनियर सेक्शन इंजीनियर) प्रदीप मिंज व मेट संतराम को निलंबित कर दिया गया है. रेल प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. मामले में कुछ और कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है।

घटना शुक्रवार की शाम पांच बजे की है. पोरबंदर-शालीमार हापा एक्सप्रेस डाउन लाइन पर हावड़ा की ओर जा रही थी. जयरामनगर से लटिया के बीच किमी 698/20ए-698/18 ए के बीच पहुंची, तभी ट्रेन चालक की नजर वहां इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों पर पड़ी. कर्मचारी रेलडाली से कुछ सामान हो रहे थे. उन्हें ट्रैक से हटाने के लिए सीटी भी बजाई गई. बार-बार सीटी बजाने के बाद भी कर्मचारी नहीं हटे और न ही रेलडाली हटाई गई. चालक ने आनन-फानन में आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया. लेकिन, इसके बाद भी रेलडाली से टकराने के बाद ट्रेन खड़ी हुई. इस घटना में किसी तरह जनहानि तो नहीं हुई। लेकिन, रेल प्रशासन की नजर में यह बेहद गंभीर मामला है. एक तरह हजारों यात्रियों की जान से खिलवाड़ है. यही कारण है कि ट्रेन चालक के घटना को लेकर अकलतरा में मेमो देने के बाद तत्काल चार सदस्यीय टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए. जांच में यह निष्कर्ष निकला कि घटना मेट संतराम की लापरवाही के कारण हुई है. इस घटना के लिए मेट संतराम और मुंशी के अलावा मौके पर मौजूद सभी कर्मचारी जिम्मेदार हैं. चूंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रदीप मिंज के दिशा-निर्देश पर संतराम के द्वारा काम कराया जा रहा था. वहीं लगभग तीन बजे सीनियर सेक्शन इंजीनियर मिंज मेट संत राम को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर घटना स्थल से कुछ दूर दूसरे कार्य का निरीक्षण करने के लिए चले गए।

लेटर बम: पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के निशाने पर कलेक्टर, लगाए 8 गंभीर आरोप, सीएम को पत्र लिख कहा- तीन दिन में हटाएं नहीं तो...

रायपुर, 23 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कलेक्टर को तत्काल पद से हटाने की मांग की है, अन्यथा शासन-प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कंवर ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर 'हिटलरशाही' तरीके से प्रशासन चला रहे हैं, और उनके खिलाफ सैकड़ों गंभीर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। ननकीराम कंवर ने पत्र में विस्तार से कलेक्टर पर लगाए गए आरोपों का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि 40,000 स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से अरबों रुपये की ठगी का मामला हो चुका है, जिसमें कलेक्टर की सीधी संलिप्तता है। इसी तरह, मालगांव और रलिया क्षेत्रों में फर्जी मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपये की अनियमितता भी कलेक्टर के इशारे पर की गई। कंवर ने कहा, कलेक्टर भाजपा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। एक पत्रकार के मकान को जमीदोज कर दिया गया, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं के राइस मिल और पेट्रोल पंप को मनमाने ढंग से सील किया गया।

यह विवाद नया नहीं है। पहले भी कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को एक फेसबुक पोस्ट के लिए नोटिस जारी किया था। कलेक्टर का तर्क था कि वह पोस्ट प्रशासन की छवि को धूमिल करती है और सामाजिक वैमनस्य फैलाने की मंशा रखती है। जुलाई 2025 में जारी इस नोटिस ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी थी। इसके अलावा, अगस्त 2024 में अतिक्रमण हटाने के दौरान ननकीराम कंवर और कलेक्टर के बीच तनाव चरम पर पहुंचा था, जब कंवर ने एक वायरल वीडियो में अधिकारियों पर 'जूते से मारने' की बात तक कह डाली थी। ननकीराम कंवर ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि कलेक्टर को राज्य सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी, अगर तीन दिनों के भीतर कलेक्टर का तबादला नहीं हुआ, तो हम बड़े स्तर पर जन आंदोलन छेड़ देंगे। इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होंगे।